India., State Trading Corpn. of India, Indian Oil Corporation Ltd., are to sign MOU for 1989-90.

The increase in the prices of coal has been necessitated because of increase in the cost of production due to escalation in wages on account of VDA, stores, capital cost etc. The premium on superior grades produced in Raniganj and Korea Rewa fileds has been levied in view of the scarcity of these types of coal in relation to the demand for them.

छोटी कारों का निर्माण

532. **श्री अजीत जोगी:**
श्री पृथ्वी माझी:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में मारुति कारों की कीमतें पुनः बढ़ा दी गई हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि मारुति कारों का निर्माण देश में इसलिये प्रारम्भ किया गया था ताकि मध्यम वर्गीय लोगों को कम कीमत पर छोटी कार उपलब्ध हो सके;

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति में मारुति उद्योग लिमिटेड के सफल न रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या मारुति उद्योग लि० की इस प्रकार की कारें बनाने में असफलता को देखते हुए मध्यमवर्गीय लोगों के लिये इन कारों के वर्तमान मूल्यों की तुलना में कम कीमत की छोटे साइज की कारें बनाये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव): (क) और (ख) जी हां। मारुति वाहनों के मूल्य 16-1-89 से, अमरीकी डालर की तुलना में रुपये में कमी तथा कच्चे माल और खरीदे जाने वाले हिस्से पुर्जों की लागत में वृद्धि के कारण बढ़ाए गए थे।

(ग) और (घ) मारुति वाहनों के निर्माण के मुख्य उद्देश्यों में मोटर गाड़ी उद्योग के आधुनिकीकरण के साथ ईंधन क्षम वाहनों का उत्पादन तथा आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य मोटर वाहनों का उच्च उत्पादन शामिल हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड अपनी परियोजना रिपोर्ट में दिए गए लक्ष्यों से कहीं अधिक ईंधन क्षम वाहनों को, सारे भारतवर्ष के लोगों को अन्य अच्छे स्थापित माडलों की कीमत से कम मूल्य पर, उपलब्ध कराने में सफल रहा है।

(ङ) सवारी कारों का मूल्य कच्चे माल हिस्से पुर्जों और अन्य अन्तर्वस्तुओं की लागत के साथ-साथ, वित्तीय लेविया जैसे विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है।

मध्य प्रदेश में बिरसिंगपुर पाली में पात विद्युत गृह का निर्माण

533. **श्री अजीत जोगी:**
श्री पृथ्वी माझी:

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बिरसिंगपुर पाली नामक स्थान पर बन रहे ताप विद्युत गृह के निर्माण की प्रगति किसी न किसी कारण से बहुत धीमी रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आरम्भ, उक्त ताप विद्युत गृह के निर्माण में कितने वर्ष लग जाने थे और तब से अब तक, कितने व्यतीत हो चुके?

ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) संजय गांधी (बीरसिंह पुर) ताप विद्युत परियोजना के 210-210

मेगावाट के यूनिट-एक व यूनिट-दो को प्रारम्भ में क्रमशः वर्ष 1985-86 और 1986-87 में चालू करने की परिकल्पना की गई थी।

मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने बायलर सप्लाई के लिए मैसर्स ए०बी०एल० तथा टर्बाइन के लिए मैसर्स भेल को आशय पत्र जारी किए हैं। मैसर्स ए०बी०एल० ने अक्तूबर, 1986 में बायलर की सप्लाई रोक दी थी और वित्तीय कठिनाइयों के कारण परिसमापन के लिए आवेदन किया था और इस प्रकार परियोजना के क्रियाकलाप वस्तुतः ठप्प हो गए थे। भूमि अधिग्रहण करने तथा विभिन्न आनुसंगिक उपस्कर के लिए आर्डर/सिविल कार्यों के लिए ठेकों को अंतिम रूप देने में विलम्ब होने जैसे घटकों से भी परियोजना क्रियान्वयन कार्यक्रम पर कुप्रभाव पड़ा है।

मैसर्स ए०बी०एल० के पुनरूत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा की गई शुरूआत के परिणामस्वरूप कम्पनी **पुनः बायलर सप्लाइ करने के लिए सहमत हो गई है।** मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने टर्बोजिनेरेटर उपस्कर एवं आनुषंगिकों का निर्माण कार्य जारी रखने के लिए मैसर्स भेल को सलाह दी है। निर्माण कार्यक्रम एवं बायलर **और टर्बोजिनेरेटर उपस्करों के डिस्पैच कार्यक्रम को** मद्देनज़र रखते हुए दोनों यूनिटों को **अब** 1991-92 में चालू किए जाने की आशा है।

"ग्रोथ सेन्टर योजना" को लागू किये जाने के परिणामस्वरूप धीमा उद्योगीकरण

534. **श्री अजीत जोगी:**
श्री पृथ्वी माझी:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि **जबसे** "नो इण्डस्ट्रीज डिस्ट्रिक्ट" योजना के साथ साथ "ग्रोथ सेन्टर योजना" सरकार द्वारा लागू की गयी है, तब से देश के सबसे पिछड़े "नो इंडस्ट्रीज" जिलों में उद्योगों को लगाने की गति बहुत धीमी हो गई है और इसके परिणामस्वरूप, ऐसे जिलों का औद्योगिकरण लगभग रूक सा गया है,

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) "ग्रोथ सेन्टर योजना" के प्रारम्भ होने के पश्चात, "नो इंडस्ट्रीज" जिलों में उद्योग लगाने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने लाइसेंस मंजूर किए गए हैं,

(घ) "ग्रोथ सेन्टर योजना" अन्तर्गत कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और कितने लाइसेंस मंजूर किए गए हैं, और

(ङ) क्या यह सच है कि "ग्रोथ सेन्टर योजना" का लाभ उन जिलों को नहीं मिल रहा है जो अपेक्षाकृत पिछड़े हैं?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) "उद्योग रहित जिलों" में उद्योगों की स्थापना करने के लिए वर्ष 1985 से 1988 के दौरान कुल 540 आशय पत्र तथा 142 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। यदि औद्योगिक लाइसेंस संबंधी कोई आवेदन नहीं है तो "उद्योग रहित" जिलों में औद्योगिक परियोजनाएं लगाने के लिए प्राप्त आवेदनों को कभी नामंजूर किया जाता है।

(घ) और (ङ) नई "विकास केन्द्र" योजना हाल ही में घोषित की गयी है तथा विकास केन्द्रों का पता लगाने हेतु राज्य सरकारों से अपने प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। अतः नये विकास केन्द्रों में परियोजनाएं स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेंसों का मामला अभी तक नहीं उठा है।

Production of Coal

535. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the estimated Statewise demand and consumption of coal in the country at present;

(b) estimated production of coal at present in the country;

(c) number of new coal mines which have been located in the country during the last one year;